



## दैनिक संपादकीय विश्लेषण

### विषय

---

स्मार्ट शहरों का बाढ़ग्रस्त सड़कों में  
परिवर्तित होने का कारण

---

## स्मार्ट शहरों का बाढ़ग्रस्त सड़कों में परिवर्तित होने का कारण

### संदर्भ

- स्मार्ट सिटी मिशन के शुभारंभ के एक दशक पश्चात, जिसका उद्देश्य 100 भारतीय शहरों को दक्षता और स्थिरता के मॉडल में बदलना था, कई भारतीय शहरों में बाढ़ ने लचीले शहरों के बजाय कमजोर बुनियादी ढांचे और चयनात्मक सौदर्यकरण को उजागर किया।

### स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM) के बारे में

- इसे जून 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य 100 शहरों को नागरिक-अनुकूल, सतत और तकनीकी रूप से उन्नत शहरी मॉडल में बदलना था।
- यह अन्य राष्ट्रीय पहलों जैसे AMRUT, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया और सभी के लिए आवास के साथ सेरिखित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि एकीकृत शहरी विकास सुनिश्चित किया जा सके।
- इसने प्रभावशाली परिणाम दिए हैं — स्मार्ट सड़कें, एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र (ICCCs), और डिजिटल बुनियादी ढांचा, जिसमें ₹1.64 लाख करोड़ से अधिक की राशि 8,000+ परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई है।

### विन्ताएं और मुद्दे

- शहरी दबाव:** विश्व बैंक के अनुसार, भारत की शहरी जनसंख्या 2020 में 480 मिलियन से बढ़कर 2050 तक लगभग 951 मिलियन हो जाएगी।
  - दिल्ली और मुंबई जैसे मेगासिटी लगातार फैल रहे हैं, जबकि भुवनेश्वर, इंदौर और कोयंबटूर जैसे टियर-2 शहर नए विकास केंद्र के रूप में उभर रहे हैं।
  - शहरी दबाव के कारण शहरों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जैसे:
    - बिना योजना के निर्माण के कारण जाम नालियां;
    - आवास की कमी के कारण अनौपचारिक बस्तियाँ;
    - बढ़ते ट्रैफिक के कारण परिवहन प्रणाली की विफलता।
- प्राथमिकताओं का बदलाव:** SCM ने 'स्मार्टनेस' के छोटे द्वीपों में निवेश किया — डिजिटाइज्ड स्ट्रीटलाइट्स, पुनर्निर्मित फ्लाईओवर, और केंद्रीकृत कमांड सेंटर — लेकिन लचीलापन निर्माण की बजाय।
  - बाढ़, जल निकासी और स्स्ती आवास जैसी मूलभूत समस्याएं अनदेखी रह गईं।
  - इसने प्रवासन को समाहित करने में सक्षम सतत सैटेलाइट शहरों के निर्माण का अवसर गंवा दिया, और सौदर्यकरण को प्राथमिकता दी।
- लचीलापन की कमी:** अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) को SCM के पूरक के रूप में डिज़ाइन किया गया था, जो जल आपूर्ति, सीवरेज, तूफानी जल निकासी और हरित स्थानों जैसे मुद्दों को संबोधित करता है।
  - इसके दूसरे चरण में ₹2.9 लाख करोड़ के उच्च आवंटन के बावजूद, शहर अभी भी मानसून के दौरान बाधित हो जाते हैं।
  - समस्या धीमी कार्यान्वयन और अलग-अलग योजनाओं के अलगाव में है — जो संभवतः ही कभी एक समेकित रणनीति में एकीकृत होती है।
- ग्रीनफिल्ड अवसरों की उपेक्षा:** अधिकांश SCM प्रयास वर्तमान महानगरों के पुनर्निर्माण पर केंद्रित रहे, जबकि नए, समग्र शहरी केंद्रों के निर्माण जैसे ग्रीनफिल्ड अवसरों को नजरअंदाज किया गया।
  - राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) के अंतर्गत विकसित औद्योगिक केंद्रों का फोकस वित्त और उद्योग पर रहा, जबकि समावेशी एवं आवास-प्रेरित विकास को अपेक्षित महत्व नहीं मिला।

- **संरचनात्मक चुनौतियाँ:** शहरों को विशेष प्रयोजन वाहन (SPVs) — नौकरशाहों या निजी हितधारकों द्वारा संचालित कॉर्पोरेट संस्थाएं — स्थापित करने की आवश्यकता थी, ताकि परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा सके।
  - इस प्रक्रिया में चुने हुए नगरपालिका संस्थानों की भूमिका सीमित कर दी गई, जिससे लोकतांत्रिक जवाबदेही और जन सहभागिता पर प्रश्नचिह्न लग गया।

### स्मार्ट सिटीज़ मिशन और बाढ़ प्रबंधन

- **क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क (CSCAF):** इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा लॉन्च किया गया था।
  - यह शहरों का मूल्यांकन करता है कि वे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कितने तैयार हैं, जिसमें बाढ़ जोखिम भी शामिल है, निम्नलिखित संकेतकों के माध्यम से:
    - जल प्रबंधन,
    - शहरी नियोजन,
    - जैव विविधता।
  - इसमें शामिल हैं:
    - SCADA सिस्टम के माध्यम से तूफानी जल की निगरानी;
    - क्षेत्र-आधारित विकास परियोजनाएं जिनमें हरित बुनियादी ढांचा और पारगम्य सतहें सम्मिलित हैं;
    - बाढ़ शमन रणनीतियों को दस्तावेज़ करने वाले ज्ञान उत्पाद और केस स्टडी।

### आगे की राह

- **पुनर्निर्माण नहीं, सृजन:** भारत की शहरी नीति को पुनर्निर्माण से हटकर सृजन की ओर अग्रसर करना आवश्यक है, तथा शै़ोन्जेन की तरह नए, लचीले और किफायती शहरों का निर्माण करने की आवश्यकता है, जो लोगों एवं निवेश दोनों को आकर्षित करें।
  - प्रगति को जीवन की सहजता, सामर्थ्य और शासन के आधार पर मापा जाना चाहिए।
- **विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन:** नए शहरों को व्यवहार्य बनाने के लिए, सरकारें वित्तीय नवाचार अपना सकती हैं:
  - प्रारंभिक वर्षों में संपत्ति कर और स्टांप शुल्क में कटौती;
  - आवास और व्यवसाय के लिए अनुमोदनों को सरल बनाना;
  - सतत निर्माण के लिए प्रोत्साहन।
- **स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM) को भारत की बदलती शहरी चुनौतियों के साथ पुनः संरेखित करना**
  - योजना और निगरानी में नागरिक भागीदारी को फिर से केंद्रित करना;
  - डिजिटल डैशबोर्ड से आगे बढ़कर जलवायु अनुकूलन, स्स्ती आवास और समावेशी गतिशीलता जैसे पैन-सिटी समाधान का विस्तार करना;
  - नगरपालिका क्षमता को सुदृढ़ करना और SPVs को स्थानीय शासन के साथ एकीकृत करना;
  - प्रकृति-आधारित समाधान और हरित बुनियादी ढांचे के माध्यम से स्थिरता को प्राथमिकता देना;
  - केंद्रीय व्यापार जिलों और अभिजात्य क्षेत्रों से परे समावेशी विकास सुनिश्चित करना।

Source: BL

### दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

**प्रश्न:** स्मार्ट सिटीज़ मिशन ने भारत में शहरी बाढ़ में किस प्रकार योगदान दिया है, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अबसंरचना नियोजन, शासन मॉडल और पर्यावरणीय स्थिरता की भूमिका पर चर्चा कीजिए।